Integral Research
(ISSN: 3048-5991) Coden: IRABCA

Research Article
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed Multidisciplinary Journal)
Journal home page: https://integralresearch.in/
Vol. 02, No. 11, November. 2025

# यूपीआई के बढ़ते उपयोग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

[1]डॉ. राम शंकर पाण्डेय ✉ [2]डॉ० रघुबीर सिंह

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) स्वामी शुकदेवानन्द कॉलेज शाहजहाँपुर
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) ठाकुर रोशन सिंह संघटक राजकीय महाविद्यालय नवादा, दरोबस्त,कटरा (शाह०)
**DOI:**

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली का सबसे बड़ा और आसान माध्यम बन चुका है। 2016 में लांच होने के बाद से यूपीआई ने देश को तेजी से एक नकद प्रधान अर्थव्यवस्था से डिजिटल पेमेंट अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इस शोध पत्र के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों को पता किया जाएगा। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, सरकारी राजस्व, वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन, लघु एवं कुटीर उद्योग, उपभोक्ता व्यवहार, डिजिटल अबसंरचना नीति सुधार एवं साइबर सुरक्षा जैसे अनेक बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा।

**मुख्य शब्द :** आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन, लघु एवं कुटीर उद्योग, उपभोक्ता व्यवहार, डिजिटल अवसंरचना, क्यूआर कोड, इंश्योरेंस मार्केट, डिजिटल पेमेंट स्तम्भ आदि।

## प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में जिस गति से डिजिटलाइजेशन की दिशा में अग्रसर है विश्व के लिए एक चुनौती है भारत सरकार की नीतियों एवं 2016 की नोटबंदी ने भारत को तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की दिशा की ओर अग्रसर किया है इस परिवर्तन के केंद्र में अनेक माध्यमों को माध्यमों को सराहा गया परंतु उनमें से यूपीआई सरल तीव्र और कम लागत वाला भुगतान ढांचा साबित हुआ है यह एक ऐसी प्रणाली है जो बैंक खातों को मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़कर बिना एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग व्यक्तिगत मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड द्वारा लेनदेन कर सकता है भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले विविध सामाजिक आर्थिक ढांचे वाले देश के लिए यूपीआई का महत्व सबसे अधिक है क्योंकि यूपीआई केवल भुगतान को सरल और तीव्र नहीं बनाता बल्कि यह आर्थिक गति पारदर्शिता वित्तीय समावेशन और डिजिटल सुरक्षा के नए कामयाब आयाम भी प्रस्तुत करता है। यह भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं कर राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए सर्वोत्तम माध्यम है।

## यूपीआई का इतिहास और विशेषताएं

यूपीआई को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया 2016 में पहली बार इस बैंक टू बैंक भुगतान के डिजिटल विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया यह प्उउमकपंजम चंलउमदज`मतअपबम पर आधारित है इसमें 24 घंटे एवं सप्ताह में सातों दिन लेनदेन किया जा सकता है। इसको केबल मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड का उपयोग करके प्रयोग करते हैं इसका शून्य अथवा बहुत कम शुल्क है। इसका टोल फ्री नंबर 1800–1201–740 अथवा 022–45414740 है नए नियम के तहत कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस पेमेंट के लिए प्रति लेनदेन सीमा ₹2 लाख से बढ़कर ₹5 लाख कर दी गई है जबकि दैनिक सीमा 10 लाख रुपए है इसका विस्तार गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप में माना जाता है यूपीआई को अब फ्रांस, सिंगापुर, नेपाल जैसे कई देशों ने स्वीकार किया है। यह भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी मजबूत करता है। इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है।

## यूपीआई 2.0

इस क्रातिकारी भुगतान प्रणाली का नया संस्करण है जिसमें नयी–नयी सुविधाएं और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया हे इसके कारण डिजिटल लेन–देन अधिक सफल और सम्बद्व बनाने की नयी सम्भावनाओं और क्षमताओं का विकास होगा। इसमें ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ भुगतान अनुरोध के साथ–साथ चालान भी भेजा जा सकेगा। सबसे मुख्य बात यह है कि अतिरिक्त प्राप्तकर्ता के अधिसूचनाओं के माध्यम से सुरक्षित नही होने से ग्राहकों को सूचित किया जाता हैं।

Received **30 October 2025**; Accepted **25 October 2025**. Available online: **30 November 2025**. Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Integral Research
(ISSN: 3048-5991) Coden: IRABCA
Research Article
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed Multidisciplinary Journal)
Journal home page: https://integralresearch.in/
Vol. 02, No. 11, November. 2025

**यूपीआई के आर्थिक प्रभाव**

भारतवर्ष में हर वर्ष करोड़ों हजारों रुपए नोट प्रिंटिंग एटीएम भरने सुरक्षा आदि पर खर्च होते थे यूपीआई ने इसमें कमी लाई है नकद जमा निकासी में लगने वाला समय मानव संपदा संसाधन और परिचालन लागत भी घट गई है। यूपीआई से भुगतान डिजिटल हो जाता है जिससे लेनदेन पारदर्शी होता है इसमें कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता जिससे कर में वृद्धि हुई है और सरकारी राजस्व में फायदा हुआ है। यूपीआई छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित हुई है उन्हें तुरंत खाते में पेमेंट मिल जाता है इससे लाखों दुकानदार रेडी पटरिया वाले ट्रांसपोर्टर आदि औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं। यूपीआई ने एमएसएमई सेक्टर को रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटल बनाया है। इसके माध्यम से फिनटेक सेक्टर साइबर सुरक्षा डिजिटल कस्टमर सर्विस बैंकिंग टेक्नोलॉजी पेमेंट गेटवे डाटा एनालिसिस स्टार्टअप केंद्र आदि क्षेत्रों में लाखों नई नौकरियां पैदा हुई है जिसने भारत के तकनीकी रोजगार को मजबूत बनाया है। यूपीआई ने खरीदारी की संस्कृति को डिजिटल बना दिया है युवाओं में नकद रखने की आदत कम हुई है छोटे खर्चे भी डिजिटल हो गए हैं। ई–कॉमर्स का उपयोग बढ़ गया है जिससे उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव आया है। यूपीआई ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में क्रांतिकारी सिद्ध हुआ ग्रामीण दुकानदार क्यूआर कोड से भुगतान ले रहे हैं। किसानो के सीधे बैंक खाते में भुगतान आ रहे हैं। महिलाएं भी डिजिटल लेनदेन में अब भागीदारी कर रही हैं। इसने डिजिटल ढांचे को मजबूत किया है तेज इंटरनेट स्मार्टफोन उपयोग सुरक्षा प्रोटोकॉल डाटा प्रबंधन आदि के कारण विश्व का सबसे सबसे सस्ता डिजिटल भुगतान देश बन गया है। यूपीआई के तेजी से अपनाए जाने से भारत की वैश्विक छवी मजबूत हुई है दुनिया भर में इसे प्दकप`जंबा मॉडल के रूप में सराह गया। भारत डिजिटल भुगतान का ग्लोबल लीडर बन चुका है।कई देशों ने भी यूपीआई को लागू किया है। यूपीआई भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दे रहा है, मुद्रा स्फीति और आर्थिक चक्र पर प्रभाव डिजिटल भुगतान उपभोग बढ़ाता है जिससे मांग और उत्पादकता बढ़ती है आर्थिक चक्र तेज होता है अगर गौर से देखा जाए तो यूपीआई से प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व फायदा हो रहा है।

यूपीआई के भारतीय बाजार के प्रमुख आंकड़े निम्न है

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंषियल सर्विसेज (DFS) dh Data Snapshot रिपोर्ट में NPCI/RBI के द्वारा मासिक एवं वार्षिक निम्न आंकड़े दिये गए है:–

| वर्ष (2025 में) माह | लेन–देन (बिलियन में) | वैल्यू (लाख–करोड़ में) |
|---|---|---|
| जनवरी | 16.99 | 23.48 |
| फरवरी | 16.11 | 21.96 |
| मार्च | 18.03 | 24.77 |
| अप्रैल | 18.67 | 24.77 |
| मई | 18.68 | 25.14 |
| जून | 18.39 | 24.03 |
| जुलाई | 19.47 | 25.08 |
| अगस्त | 20.01 | 24.85 |
| सितम्बर | 19.63 | 15.08 |
| अक्टूबर | 20.7 | 24.28 |

वार्षिक यूपीआई लेन–देन वित्तीय वर्ष यूपीआई लेन–देन की संख्या यूपीआई लेन–देन का मूल्य

| वित्तीय वर्ष | यूपीआई लेन–देन की संख्या | यूपीआई लेन–देन का मूल्य |
|---|---|---|
| 2020–21 | 2,233 करोड़ | 41 लाख करोड़ |
| 2021–22 | 4,597 करोड़ | 84 लाख करोड़ |
| 2022–23 | 8,375 करोड़ | 139 लाख करोड़ |
| 2023–24 | 13,116 करोड़ | 200 लाख करोड़ |
| 2024–25 (15 नम्बवर तक) | 18,587 करोड़ | 261 लाख करोड़ |

**यूपीआई की चुनौतियां**

आज यूपीआई लेनदेन का सशक्त माध्यम है परंतु भारत जैसे देश में अनेक चुनौतियां निम्न हैं–

1– साइबर सुरक्षा धोखाधड़ी और फर्जी कॉल्स आम नागरिकों को परेशान करते हैं।

2– ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट समस्या कमजोर नेटवर्क सर्वर लोड और तकनीकी दिक्कतें डिजिटल भुगतान में सबसे बड़ी बढ़े हैं।

3– डिजिटल साक्षरता का अभाव बुजुर्ग और अनपढ़ लोगों को एक का उपयोग करने में बाधा पहुंचती है।

4– बैंक और कंपनियां लंबे समय तक बिना शुल्क संचालित नहीं हो सकती।

**भविष्य की संभावनाएं–**

Received **30 October 2025**; Accepted **25 October 2025**. Available online: **30 November 2025**. Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Integral Research
(ISSN: 3048-5991) Coden: IRABCA
Research Article
(Peer-reviewed, Open Access & Indexed Multidisciplinary Journal)
Journal home page: https://integralresearch.in/
Vol. 02, No. 11, November. 2025

यूपीआई का भविष्य उज्ज्वल हैं इसमें प्रौद्योगिकी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच में भी आर्थिक विकास की सम्भावनाएं है। भविष्य में बायोमेट्रिक प्रमाणीकृत, वॉयस–सक्षम लेनदेन और विभिन्न देषों के साथ साझेदारी के माध्यम से यूपीआई का वैष्विक विस्तार देखा जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, और धोखाधड़ी और भष्ट्राचार से निपटने के लिए सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर भी जोर दिया गया है। सरकारी योजनाओं में यूपीआई का उपयोग यूपीआई क्रेडिट लाइन यूपीआई आधारित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान यूपीआई आधारित माइक्रो लोन कारोबारी के लिए यूपीआई आधारित मतच सिस्टम के द्वारा अग्रसर हो सकता है। यूपीआई भारत को 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में भी अपना योगदान दे सकता है।

## निष्कर्ष

भारत में यूपीआई की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है 85 प्रतिषत डिजिटल ट्रांजेक्शन बताते हैं कि यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का स्तंभ बन चुका है बहुत सारे लोग यूपीआई को छोटे–छोटे खर्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े लेनदेन के लिए भी उपयोग कर रहे हैं यूपीआई ने भारत की आर्थिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव किया है यह एक भुगतान प्रणाली नहीं रही बल्कि आर्थिक पारदर्शिता रोजगार उद्यमिता वित्तीय समावेशन सरकारी राजस्व आज क्षेत्र में परिवर्तन का मुख्य कारण बन चुकी है यूपीआई आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकती है यह भारत को एक डिजिटल पारदर्शी और मजबूत अर्थव्यवस्था में बदलने की क्षमता रखता है। इसके माध्यम से धोखाधड़ी एवं भष्ट्राचार पर अंकुष लगाकर पारदार्षिता, निष्पक्षता एवं कर राजस्व में बढ़ोत्तरी हो रही हैं।

## संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. The Making of UPI: The Incredible Story of India's Digital Revolution- Jagdish R kakkaria
2- UPI: One Nation One Payment- Nandan nilekani and T. Venkatesh
3- The Art of India's Digital Revolution- Nandan nilekani
4- Digital Payments in India- R Kumar
5- India Stack: Rebooting Governance- Nandan nilekani and Pramod Verma
6- Fintech Future- Susan Chappy and Jenison Lodge
7- Reserve Bank of India (RBI) annual report 2021 to 2024
8- Ministry off electronics and IT - India digital ecosystem studies
9- Niti Aayog- India's digital transformation reports- 2023to2024
10- World Bank- digital financial services Reports
11- IMF - fintech Notes and working papers
12- UNCTAD - digital economy report 2024
13- NPCI - National payments corporation of India upi product statics monthly and annual reports- 2020 to 2024
14- OECD digital economy reports 2024

Received **30 October 2025**; Accepted **25 October 2025**. Available online: **30 November 2025**. Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License